ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-7* August- 2020
Innovation The Research Concept

पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की राजनीति

Politics of Environment and Natural Resources

Paper Submission: 15/08/2020, Date of Acceptance: 25/08/2020, Date of Publication: 26/08/2020

श्वेता सिंह
सहायक प्राध्यापिका,
राजनीति विज्ञान विभाग,
आइसेक्ट विश्वविद्यालय,
हजारीबाग, झारखण्ड, भारत

सारांश

पर्यावरण एक ऐसा प्राकृतिक परिवेश है, जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित एवं नष्ट करने में मदद करती है। प्राकृतिक पर्यावरण हमारे जीवन के अस्तित्व में एक बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन मनुष्य की कुछ स्वार्थी गतिविधियों ने पर्यावरण को समय–समय पर प्रभावित किया है। प्रकृति, हमें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराती है और मनुष्य अपनी जीविकोपार्जन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। और तो और, प्राकृतिक संसाधन जो मनुष्य की दैनिक आवश्यकता है इस पर हमारे देश में समय–समय पर राजनीति होते आई है। कभी प्राकृतिक संपदाओं के दोहन को लेकर तो कभी प्राकृतिक संपदाओं की समृद्धि के लिए, वर्तमान समय में पर्यावरण और प्राकृतिक संपदाओं की राजनीति भारत जैसे देश में आम बात सी हो गई है।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि आदिम मानव अपने पर्यावरण से प्राप्त वनस्पतियों एवं पशुओं पर निर्भर था। उस समय जनसंख्या का धनत्व काफी कम था, मनुष्य की आवश्यकताएँ सीमित थी तथा औद्योगिक विकास का स्तर नीचे था, परन्तु वर्तमान में स्थिति अलग है, मनुष्यों की आवश्यकताएँ असीमित हो चुकी है, जनसंख्या का घनत्व रफ्तार पकड़ चुका है, तथा औद्योगिक विकास मानव की पहचान बन चुकी है वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास द्वारा मनुष्य जीविकोपार्जी संसाधनों के अतिरिक्त उत्पादन के संसाधनों के दोहन में लगा है अतः यह आशंका उत्पन्न होने लगी है कि कहीं ये संसाधन शीघ्र समाप्त न हो जाए और पूरी मानवता के जीवन पर प्रश्नचिह्न न लग जाए।

पर्यावरण और विकास को लेकर सबसे पहले 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन ब्राजील के नगर रियो–डी–जेनेरिया में हुआ था। इस सम्मेलन में 170 देशों, कई स्वयंसेवी संघों तथा हजारों बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भाग लिया था, जिसमें एजेंड़ा तैयार कर इस बात पर सहमति हुई की आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाया जाए।

पर्यावरण से संबंधित जो भी नियम बनाए जाते हैं वो सरकार या संस्थाओं के द्वारा बनाये जाते हैं, इसलिए पर्यावरण को राजनीति का विषय भी कहा जाता है। संसाधन को हासिल करने के लिए जो राजनीति की जाती है, उसे ही प्राकृतिक संसाधनों की राजनीति कहते हैं। देखा जाय तो वैश्विक महामारी कोरोना संकट भी इसी का नतीजा है।

The environment is a natural environment that helps develop, nurture and destroy life on Earth. The natural environment plays a big role in the survival of our lives, but some of the selfish activities of humans have affected the environment from time to time. Nature provides us natural resources to meet our daily needs and man exploits natural resources for his livelihood. Moreover, politics has been taking place in our country from time to time on the natural resource which is the daily requirement of man. Sometimes with regard to exploitation of natural assets and sometimes for the prosperity of natural assets, in the present time environment and politics of natural assets have become common in a country like India.

History testifies that primitive humans depended on flora and animals derived from their environment. At that time the wealth of the population was very low, human needs were limited and the level of industrial development was low, but at present the situation is different, the needs of human beings have become unlimited, the density of population has gained momentum, and industrial development of human beings. Identification has been made through scientific and technological development, human beings are engaged in exploiting the resources of production in addition to livelihood resources, so there is a possibility that these resources will be exhausted quickly and the life of entire humanity will be questioned.

The first earth conference on environment and development was held in 1992, also known as the Rio Conference. The conference took place in the Brazilian city of Rio-de-Janeiro. The conference was attended by 170 countries, many voluntary associations and thousands of multinational companies, in which it was agreed to prepare an agenda not to harm the environment for economic development.

All the rules related to environment are made by the government or institutions, hence environment is also called the subject of politics. The politics that is done to acquire resources is called politics of natural resources. If seen, the global epidemic corona crisis is also the result of this.

मुख्य शब्द :जिम्मेदार, आवश्यकताएँ, जीविकोपार्जन, जलवायु, पदार्थ, वन्यजीव, पर्यावरणीय, पारिस्थितिवाद, विचारधारा, परिवर्तन।

Responsible, Requirements, Livelihood, Climate, Matter, Wildlife, Environmental, Ecologicalism, Ideology, Change.

प्रस्तावना

मुख्य रूप से पर्यावरण हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रकियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीडे–

मकोडे के साथ– साथ सभी जीव – जंतु और पेड–पौधे भी आ जाते हैं अजैविक धटकों में जीवनरहित तत्व और उनसे जुडी प्रकियाएँ भी आती हैं, जैसेः चटाने, पर्वत, नदी, हवा, और जलवायु के तत्व इत्यादि। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय संबंध भी होता है। एक जीवधारी की उत्पति और विकास भी बहुत हद तक पर्यावरण से प्रभावित होती है। प्राकृतिक संसाधन वो प्राकृतिक पदार्थ है, जो अपने प्रारंभिक और प्राकृतिक रुप में मूल्यवान माने जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है, कि प्राकृतिक संसाधन कितना उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी है। प्राकृतिक संसाधनों में मुख्य रुप से मिटटी, लकडी, खनिज तेल, के अलावा अन्य वो पदार्थ शामिल हैं जो धरती से प्राप्त होते है।

मनुष्य द्वारा तकनीकी विकास तथा आर्थिक विकास के उद्येश्य से किये गये व्यापक छेडछाड के क्रियाकलापों के कारण प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बिगडता चला जाता है। वर्तमान समय मे पर्यावरण संरक्षण के लिए जाग्ररूकता की आवश्यकता है आज पर्यावरण एक जरूरी ही नही बल्कि एक ज्वलंत मुद्दा है, जिसका हल है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम सफल सिद्ध होगा, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तथा आर्थिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। आने वाली पीढी को पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों का ज्ञान होना आवश्यक है।

मनुष्य अपनी अतित्व के संधर्ष के लिए निरंतर जूझता चला आ रहा है, और मनुष्य के विकास में प्रकृति ने हमेशा ही मनुष्य का साथ दिया है। लेकिन कहीं–कहीं प्रकृति का भी उसके साथ संधर्ष होता रहा है। मनुष्य का प्रकृति के साथ इतना गहरा संबंध है, कि संपूर्ण मानव जाति इससे प्रभावित होती है। आज यह एक पर्यावरणीय प्रश्न है, जिससे हमारा अस्तित्व जुडा हुवा है।**1**

भारत आज भी पर्यावरणीय संकट से गुजर रहा है। कभी हवा, तो कभी पानी का संकट, हवा की गुणवत्ता इस हद तक खराब हो गई है, कि इसके चलते देश मे बडी तादात मे लोग मर रहे हैं। विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत में जहरीली हवा के कारण शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है 2017 में देश मे आठ में से कम से कम एक मौत के लिए वायु प्रदुषण को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसी तरह देश मे दिन प्रति दिन जल प्रदुषण का स्तर बढता जा रहा है, और हमारे देश मे शिशुओं की मौत के लिए जल प्रदुषण जिम्मेदार है। भारत एक ऐसा देश है जिसे सोने की चिडिया होने का गौरव प्राप्त है, और इसका मूल कारण है कि भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, जो हमारे देश को समृद्ध बनाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश मे विकास के मुद्दों पर समय समय पर राजनीति होते ही रहती है, लेकिन वर्तमान समय में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर भी राजनीति होने लगी है।

हमारे देश में वन तथा वन्यजीव वर्तमान समय में पतन की ओर अग्रसर है। पिछले तीन दशक से हम सबने मिलकर प्राकृतिक वनों को बगीचे में बदल दिया है। इसके अलावा भूजल के मामले मे तो संकट और भी विकट प्रश्न बना हुआ है हम अभी पीने के पानी की आपूर्ति पर लगभग 80 फसदी निर्भर हैं वर्तमान मे हम भूजल संकट के निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं देश मे 640 जिलों में से 276 का भूजल फलोराइड के कारण प्रदूषित है 387 में नाइट्रेट है, 113 जिले में हैवी मेटल्स हैं और 61 जिलों में भूजल में यूरेनियम है। वर्तमान में हमारे सामने जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या आ खडी है,जो लोगों के जीवन और जीवीका के लिए खतरा है। सूखा, अत्यधिक बारिश, चक्रवात, बाढ जैसी होने वाली प्राकृतिक घटनाऐं देश के कई हिस्से को तबाह कर देती है। जिसमें 2013 में उतराखंड में, 2014 में जम्मू और कश्मीर में, 2015 में चेन्नई में और 2018 में केरल में बाढ आई थी। इन घटनाओं के कारण प्रत्येक साल सैकडों लोगों की जान चला जाती है और हजारो करोड़ रूपये का आर्थिक नुकसान होता रहता है। भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी बुरा होने वाला है।

आज देश की राजधानी दिल्ली सहित एन सी आर जैसे क्षेत्रों में धुंध एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हमें मालूम होना चाहिए कि,2015 में ही सर्वोच्च न्यायलय के द्वारा दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया गया था कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूल करे और इस वसूली से प्राप्त राशि को नई तकनीकों के प्रयोग से दिल्ली के प्रदुषण को कम करने में इस्तेमाल करें। लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार इस शुल्क के जरिए प्राप्त 700 करोड की रकम को सही जगह पर लगाने में दिल्ली सरकार पूरी तरह नाकाम रही है।**2** कांग्रेस ने वायु प्रदुषण को लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और आपातकालीन स्थिती बतलाते हुए कहा है कि वह वायु प्रदुषण के सभी स्त्रोतों को निशाने पर लेगी। वही भाजपा ने भी राष्टीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एन सी पी को एक मजबूत मिशन में बदल कर पांच साल के अंदर वायु प्रदुषण के स्तर को 35 प्रतिशत तक कम करने का वादा किया था। जबकि वायु प्रदुषण को ले कर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के एन सी पी को मजबूत करके

वायु प्रदुषण को कम करने का वादा विफल नजर आता है।[3]

प्राकृतिक संसाधनों में मूल्यवान समझे जाने वाले कोयला पर स्थिती और भी गंभीर है। कोयला उत्पादक क्षेत्रों जैसे झारखंड, मेघालय आदि क्षेत्रों में गरीब तबके के लोग अपनी जीविका के साधन को जुटाने के लिए कोयला खदानों में काम करने के लिए विवश हैं, जहां आए दिन कोयला खदानों में हादसे हो जाते हैं और जरूरी उपकरण के अभाव के कारण खदानों में फंसे मजदूरों को अपनी जान गंवानी पडती है, रैट होल की वजह से निर्दोष मजदूर अक्सर जिंदा ही दफन होते रहे हैं और जब तक इस अमानवीय किस्म के कोयला खनन पर पूरी तरह रोक नहीं लग जाती तब तक गरीब सुरक्षित नहीं हैं। वहीं राज्य की सरकारें ठोस नीति बनाने के बजाय एक – दूसरे पार्टियों पर दोषारोपण करती रह जाती है। हाल ही में मेघालय के कुछ नागरिक समाज संगठनों नें जो रिर्पोट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की है जिससे एक अलग ही तस्वीर उभर कर सामने आई है। इस रिर्पोट में बताया गया है, कि भले ही कोयला खनन पर राज्य में एनजीटी की तरफ से रोक लगाई गई है लेकिन मेघालय में कई राजनेताओं के संरक्षण में धडल्ले से कोयला खनन किया जाता रहा है।

अभी हाल ही में भाजपा की सरकार ने जल संकट को दूर करने के लिए 2022 तक स्वच्छ गंगा के लक्ष्य को प्राप्त करने का वादा किया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने गंगा सहित नदियों की सफाई के लिए बजट आवंटन को दोगुना करने का वादा किया तो है लेकिन दोनों ने ही भूजल के स्तर में सुधार लाने बात नहीं की है।

जलवायु परिवर्तन के मुददे पर कांग्रेस ने वादा किया है कि वे ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक एक्शन एजेंडा लाऐंगे। दूसरी ओर भाजपा 2022 तक 175 गीगावाट उर्जा के नवीकरण को प्राप्त करने के वादे के अलावा जलवायु परिवर्तन के मुददे पर काफी हद तक चुप है।

उपर बताए गए स्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि हम राजनीतिक दलों से कुछ अपेक्षा करे कि वे इस गंभीर प्रश्न पर विचार करे जिसमें पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन में संतुलन जैसे खास मुददो पर खुलकर बात हो, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, कि राजनीतिक दलों नें अपने पुराने विचार को ही दोहराया है, और पर्यावरण जैसे गंभीर मुददे को भी मात्र परिधीय विषय के रूप में फिर से पेश किया है।

पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य के सुधार से संबंधित विस्तृत दर्शन, एक विचारधारा तथा सामाजिक आंदोलन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्यावरण एक प्रमुख सार्वजनिक चिंता बन गई। चुनावी लोकतंत्र में नेतृत्व के राजनीतिक चक्रों के संबंध में जलवायु परिवर्तन धीमा है, जो राजनेताओं द्वारा प्रतिक्रियाओं को बाधित करता है। अंतर्राष्टीय राजनीतिक समुदाय वर्तमान में उदार सिद्धांतों पर आधारित है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पूंजीवादी प्रणालियों को प्राथमिकता देते हैं, जो त्वरित और महत्वकांक्षी जलवायु प्रतिक्रियाओं को मुश्किल बनाते हैं। बहुत बडी संख्या में लोग अपने स्वंय के हितों को सुनने और समझने में असमर्थ होते हैं।एक ओर तो लोकतंत्र में नागरिकों को पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को तथा उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए शिक्षा की कमी होती है। दुसरी ओर पर्यावरणीय शोषण और संरक्षण से, पारिस्थितिकीय गिरावट के प्रभाव से तथा पर्यावरणीय चिंताओं से लोकतांत्रिक राजनीति को आधार मिल सकता है।

भारत मे पर्यावरणीय विधि अथवा पर्यावरण विधि मुख्य रूप से उन सभी अंतर्राष्टीय,राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संधियों, समझौतों और संवैधानिक विधियों को कहा जाता है जो प्राकृतिक पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने और पर्यावरण की उपलबधता बनाये रखता है

1. भारत में पर्यावरण कानून पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 से नियमित होता है, जो एक व्यापक विधान है। इसकी रूपरेखा केन्द्र सरकार के विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के समन्वय के लिए तैयार किया गया है जिनकी स्थापना पिछले कानूनों के तहत की गई है जैसा कि जल अधिनियम और वायु अधिनियम।
2. अन्य विधियों में भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 प्रमुख है
3. एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का भी गठन किया गया हैं।[4]

प्राकृतिक संसाधनों का संबंध सीधे पर्यावरण से जुडा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कई तरह के अवधारणाओं को आंदोलनों के रूप में प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है। पर्यावरणीय राजनीति एक ऐसी राजनीतिक षडयंत्र है, जिसमें राजनीति एक ऐसा तरीका है, जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के पर्यावरणीय संसाधनों को प्राप्त किया जाता है। पर्यावरणीय राजनीति एक ऐसी राजनीति का नमूना है, जिसमें विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची हुई है और पर्यावरण विकास की भेंट चढ रहा है। यह आज से नहीं हो रहा है, वैज्ञानिकों के चेतावनी के बावजूद भी राजनीतिक लाभ जो वर्तमान में आर्थिक लाभ बन चुका है, इसके लिए सभी राष्ट अपनी जिम्मेदारियों को छोड कर बस आर्थिक लाभ के होड में लगे हुए हैं। पर्यावरणवाद या पारिस्थितिवाद, पर्यावरण संरक्षण से संबधित एक ऐसी विचारधारा तथा सामाजिक आंदोलन है जिसके द्वारा पर्यावरण के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए राजस्थान तथा देश के अन्य राज्यों में रह रहे बिश्नोई पंत के लोगों का प्रमुख योगदान रहा है, बिश्नोई पंत के लोग विष्णु अवतार जाम्भोजी के शिष्य हैं। जोधपुर के खेजडियाली गांव में 363 लोगों ने अपनी जान देकर भी पेडों की रक्षा की थी।[5]

वर्तमान समय में पूरा विश्व ही विकास की होड में सम्मिलित है। यही कारण है, कि विकास की इस बेतहाशा दौड में पिछले कुछ समय से रूस के साथ पश्चिम के देशों का संबंध दिनोंदिन बढता जा रहा है।

इन सभी मुद्दों के अतीरिक्त विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी पिछले कुछ समय से अनदेखी की जा रही है वह महत्वपूर्ण मुद्दा है पर्यावरण का। विश्व राजनीति में विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है। और विकास के इस दौर में पर्यावरण विकास की भेंट चढ जाता है। मुख्य बिंदु यह है कि विश्व राजनीति में पर्यावरणीय मुद्दा वैश्विक अस्थिरता के कारण हमेशा से कम करके आंका जाता है। वर्तमान में बाढ तथा सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों का अधिक संख्या में विस्थापन हो रहा है। जो एक गंभीर समस्या है।[6]

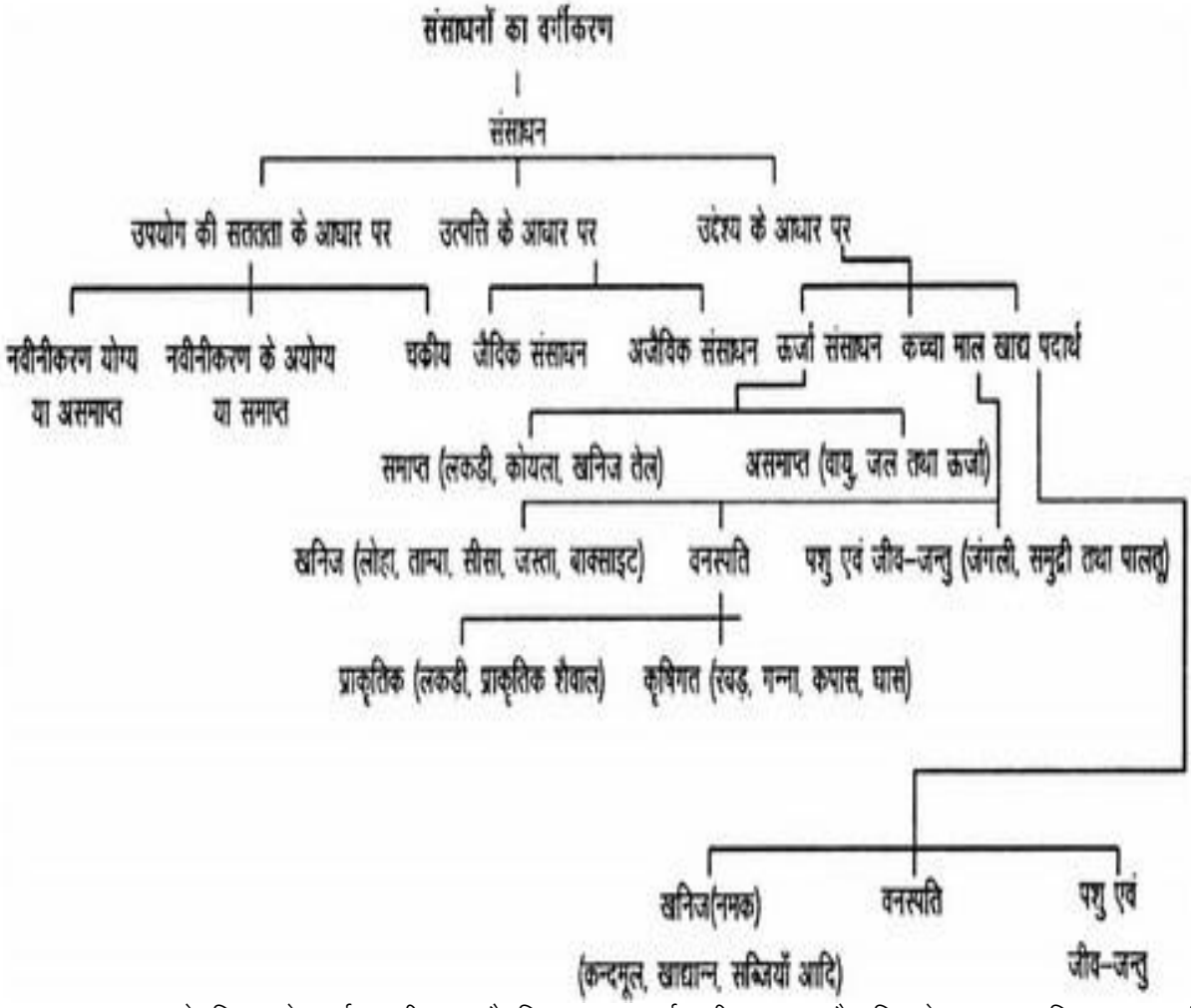

यह हमारे लिए बडे दुर्भाग्य की बात है कि जहां। एक ओर दुनिया के कई देश पर्यावरण से जुडे कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, वहीं भारत पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को लेकर कोई संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। भारत में अगर हम पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का मुद्दा उठाना चाहते हैं तो हमें लोगों की धारणाओं को बदलना होगा और हरित एजेंडे को मुख्यधारा की सियासत में लाने के लिए पहल करनी होगी जिसका पहला कदम पर्यावरण के महत्व को समझना और समझाना होगा।

मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संधर्ष से निरंतर जुझता चला आ रहा है, और प्रकृति ने उसके विकास में सदैव सहयोग दिया है, लेकिन कभी कभी प्रकृति का मनुष्य के साथ संधर्ष होता रहा है प्रकृति के साथ समाज की अंर्तक्रिया इतनी व्यापक है, कि उससे पूरी मानव जाति प्रभावित होती है। आज यह एक विकट पर्यावरणीय प्रश्न्न है, जिससे हमारा अस्तित्व जुडा है। राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण से गहरा संबंध है। ईस्टन का ऐसा मानना है, कि राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण कभी स्वतंत्र नही होता है। वह कई परिस्थितियों से घिरा होता है और उन परिस्थितियों द्वारा प्रस्तुत परिवेश के अंर्तगत ही पर्यावरण निरंतर ही क्रियाशील रहता है।[7]

अध्ययन के उद्देश्य

वर्तमान में जिस तरह से हम अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं, यह एक विकराल प्रश्न भारतीय समाज के सामने खड़ा है और इसी विकट प्रश्न का समाधान खोजना मेरे इस लेख का उद्देश्य है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन समाज में प्रगति का आधार है। ये हर दृष्टिकोण से हमारे जीवन में महत्व रखती हैं, और समाज की प्रगति में उनका भरपूर योगदान है, इसलिए उनके संरक्षण के लिए हमें जनता

को शिक्षित अवश्य करना चाहिए। ताकि देश की प्रगति हो।

हमारे राजनीतिक दल जिस तरह से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहीं हैं, वह भारत जैसे गौरवशाली देश के लिए कलंक की बात है, अतः पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए जनता में जागरूकता लाना मेरे इस लेख का मूल उद्देश्य है।

परिकल्पना

1. प्राकृतिक संसाधन हमारे प्राकृतिक धरोहर हैं, जिसकी वृहत चर्चा अपेक्षित है।
2. वर्तमान में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है।
3. वर्तमान में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन समाज में प्रगति का आधार है।
4. प्राकृतिक संसाधनों की राजनीति, पर्यावरण का एक ज्वलंत मुद्दा है।
5. भारतीय समाज की प्रगति के लिए पर्यावरण का अवलोकन जरूरी है।
6. वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की अहम भूमिका है।

अध्ययन–पद्धति

किसी भी लेख में अध्ययन–पद्धति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इससे प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता और मान्यता पर ही किसी विषय की सत्यता स्थापित होती है। प्रस्तुत लेख में मैंने अध्ययन–पद्धति के रूप में विष्लेषणात्मक, तुलनात्मक स्वरूप को अपनाते हुए, मुख्य रूप से ऐतिहासिक और वर्णनात्मक अध्ययन–पद्धति का प्रयोग किया है।

निष्कर्ष

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दृष्टि से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन काफी आवश्यक है, हमारे देश में अक्सर ही कभी तेल पर, कभी पानी पर, कभी वायु पर, तो कभी कोयला पर आये दिन समाचार पत्रों, टेलीविजन के माध्यम से राजनीतिक गर्माहट की आहट सुनाई देती है, अगर जल्द ही इस पर लगाम न लगाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब मानव जीवन समाप्त हो जायेगा और जब जीवन ही नहीं होगा तो राजनीति किसपर ?

अतः यह आवश्यक है कि पर्यावरणीय संसाधनों के उत्थान के दिशा में प्रयास किये जाय। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के बीच एक रिश्ता कायम हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि अपनी नीतियों एवं निर्णयों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के उचित बंटवारे को बढावा दे तथा मानव और प्रकृति के बीच स्थापित संबंध को और प्रगाढ बनाए। अतः एक स्वस्थ दुनिया के स्वरूप को बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण को सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *प्रो हरिमोहन ''मानव अधिकार और पर्यावरण–संतुलन '' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली–दरियागंज –21 ए*
2. *https://www.hisour.com/hi/environmental-politics*
3. *https://www.downtoearth.org.in*
4. *राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मूल से 20 अगस्त 2014 को पुरालेखित अभिगमन तिथि 22 अगस्त 2014*
5. *https://m.dailyhunt.in*
6. *https://www.drishtiias.com*
7. *शशि शर्मा .''राजनीतिक समाजशास्त्र की रुपरेखा''– 2015 पी एच एल लर्निंग प्राइवेट लीमिटेड दिल्ली।*